भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1778
29.07.2026 को उत्तर देने के लिए

साक्ष्य-आधारित शहरी नियोजन

1778. डॉ. शशि थरूरः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए उपलब्ध शहरी सांख्यिकीय आंकड़ों की पर्याप्तता, आवधिकता और सूक्ष्मता/विस्तृतता का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अद्यतन की आवृत्ति, भौगोलिक पृथक्करण के स्तर और सार्वजनिक पहुंच सहित सरकार के पास उपलब्ध रखे गए शहरी सांख्यिकीय डेटासेटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को शहरी सांख्यिकीय आंकड़ों की उपलब्धता, पहुंच या आवधिकता में अंतरालों/कमियों के संबंध में राज्य सरकारों से, विशेषकर केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा साक्ष्य-आधारित शहरी नियोजन हेतु शहरी सांख्यिकीय आंकड़ों की उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता को मजबूत करने तथा राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के माध्यम से साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण के लिए आधिकारिक सांख्यिकी की उपलब्धता, समयबद्धता और भौगोलिक स्तर पर सूक्ष्मता में सुधार हेतु निरंतर कदम उठा रहा है। राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के सर्वेक्षणों की प्रतिदर्श डिजाइन में जिला-स्तरीय अनुमान तैयार किए जाने हेतु संशोधन किया गया है।

एमओएसपीआई ने शहरी नियोजन और नीति-विश्लेषण के लिए पृथक्कृत सांख्यिकीय आँकड़े उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) और अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) के माध्यम से (जनगणना 2011 के अनुसार) 46 मिलियन प्लस शहरों के लिए भी शहरी-स्तरीय अनुमान प्रस्तुत किए हैं। अधिकांश सर्वेक्षण रिपोर्टों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अनुमान पृथक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जाता है

और इन्हें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाता है। स्थानीय नीतियों के निर्माण और क्षेत्रीय नियोजन को सुगम बनाने के उद्देश्य से, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिला-स्तरीय अनुमानों के सृजन हेतु विभिन्न राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के सर्वेक्षणों में भाग लेते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने वाले गुणवत्ता मानक, एमओएसपीआई की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप होते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सुदृढ़ प्रतिदर्श डिजाइन, एकरूप सर्वेक्षण प्रपत्र, मानकीकृत डेटा प्रसंस्करण प्रोटोकॉल और संरचित सत्यापन जाँच आदि शामिल हैं।

एमओएसपीआई को केरल सहित किसी भी राज्य सरकार से शहरी सांख्यिकीय आँकड़ों की उपलब्धता, पहुँच और आवधिकता में किसी प्रकार की कमी के संबंध में कोई अनुरोध/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

साक्ष्य-आधारित योजना के लिए राज्य सांख्यिकीय प्रणाली का समर्थन करने के लिए, एमओएसपीआई ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी सहायता, प्रतिदर्श डिजाइन, सर्वेक्षण उपकरण, क्षमता निर्माण, टैबलेट, सीएपीआई और क्लाउड सर्वर जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करना आदि शामिल हैं। सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थन (एसएसएस) के तहत, एमओएसपीआई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को उनके सांख्यिकीय कार्यों और क्षमता को मजबूत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, अर्थात सांख्यिकीय अनुप्रयोगों और आईटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना; सांख्यिकीय कर्मियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण; डेटा गुणवत्ता और दक्षता में सुधार; राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) निगरानी में भागीदारी को मजबूत करना; सांख्यिकीय आउटपुट का प्रसार और उपयोगकर्ता-निर्माता परामर्श; और आधिकारिक आंकड़ों की समयबद्धता, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार; नवीन सांख्यिकीय तकनीकों और पद्धतियों को अपनाना। इसके अलावा, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी सांख्यिकीय क्षमता और संचालन को मजबूत करने के लिए सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थन (एसएसएस) योजना के तहत सहायता भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार, केरल ने विभिन्न सांख्यिकीय गतिविधियों और आईटी बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए 2015-16 और 2024-25 के तहत 22.49 करोड़ रुपये की कुल राशि का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। राज्य के प्रस्ताव और निधि आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाया गया था और मार्च, 2026 तक 15.105 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

सांख्यिकीय रिपोर्ट और अन्य आधिकारिक सांख्यिकीय आऊटपुट को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटों एवं अन्य प्रसार मंचों, जैसे ई-सांख्यिकी, जीओआईएसटीएटीएस मोबाइल ऐप आदि के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाता है। इकाई-स्तरीय आँकड़े और उनसे संबंधित तकनीकी दस्तावेज, जैसे प्रतिदर्श डिजाइन और अन्य सर्वेक्षण प्रलेखन, भी एमओएसपीआई के माइक्रोडाटा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।

*****